

(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक ९७८-दो/२००७ निगरानी - विरुद्ध आदेश दिनांक
२३-५-२००७ पारित क्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक
४३०/२००५-०६ अप्रैल

१- हृदयलाल साहू पुत्र रूपनारायण साहू

२- जगदीश प्रसाद पुत्र जैतलाल साहू

३- प्रेमलाल पुत्र बन्धू साहू

तीनों निवासीगण ग्राम मेढोली तहसील सिंगरोली

जिला सीधी, मध्य प्रदेश

—आवेदकगण

विरुद्ध

१- नब्द सिंह पुत्र लक्खा सिंह

२- जसबिन्दर सिंह पुत्र नब्द सिंह

निवासीगण ग्राम मेढोली तहसील सिंगरोली

जिला सीधी मध्य प्रदेश

३- मध्य प्रदेश शासन

—अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री डी०एस०चौहान)

(अनावेदक क्र-१,२ के अभिभाषक श्री के०के०द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक २७ - ३ - २०१७ को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा क्वारा प्रकरण क्रमांक
४३०/२००५-०६ अप्रैल में पारित आदेश दिनांक २३-५-२००७ के विरुद्ध
म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

२/ प्रकरण का सारोंश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार सिंगरोली के
समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा १२१ के अंतर्गत प्रार्थना

✓

प्रस्तुत कर माँग रखी कि ग्राम में खेली स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 348/1 रक्का 2.832 हैक्टर है जो राजस्व अभिलेख में मध्य प्रदेश शासन के नाम पर है इस भूमि के अंश भाग 0.200 हैक्टर - 0.200 हैक्टर पर आवेदकगण १९६०-६१ से काविज होकर आबादी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं इसलिये मौके के कब्जे अनुसार हृदयलाल साहू पुत्र रूपनारायण साहू का 0.200 है पर तथा जगदीश प्रसाद का 0.200 हैक्टर पर एंव प्रेमलाल का 0.240 हैक्टर पर कब्जा दर्ज किया जाय। तहसीलदार सिंगरोली ने प्रकरण क्रमांक 41 अ-६-अ/२००४-०५ पंजीबद्ध किया तथा जॉच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक १५-६-२००५ पारित किया एंव उक्तांकित रक्के पर आवेदकगण का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विलम्ब अनावेदक क्रमांक-१ ने अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण क्रमांक १२/२००५-०६ अपील में पारित आदेश दिनांक १४-२-२००६ से तहसीलदार का आदेश दिनांक १५-६-२००५ निरस्त किया एंव अपील स्वीकार की। इस आदेश के विलम्ब आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक ४३०/२००५-०६ अपील में पारित आदेश दिनांक २३-५-२००७ से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

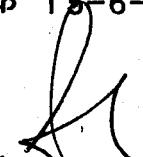
4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि जब जॉच के दौरान तहसीलदार ने आवेदकगण का कब्जा वर्ष १९६०-६१ प्रमाणित पाया है तथा आवेदकगण की आबादी के उपयोग में भूमि आ रही है मौके की साक्ष्य ली गई है पटवारी प्रतिवेदन में आवेदकगण का कब्जा प्रमाणित हुआ है एंव पूर्ण सन्तुष्टि उपरांत तहसीलदार ने आदेश दिनांक १५-६-०५ से आवेदकगण के हित में कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये हैं जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने जानबूझकर अनावेदकगण को लाभ पहुंचाने के लिये मनमाफिक अर्थ निकाल कर तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में भूल की है जिस पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक २३-५-०७ पारित करते समय ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त करने की मांग रखी।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि जब व्यवहार व्यायालय से अनावेदकगण के हित में वाद विचारित भूमि की डिकी है एंव वह भूमिस्वामी है तब व्यवहार व्यायालय के आदेश को अनदेखी करके तहसीलदार ने बेजा कब्जा दर्ज करने में भूल की है। उन्होंने तहसीलदार के आदेश को वृटिपूर्ण होना बताते हुये अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त के आदेश को सही छहराते हुये निगरानी निरस्त करने मी मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ व्यायालयों के प्रकरणों में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक २३-५-०७ में विवेचित किया है कि भूमि सर्वे कमांक ३४८/१ रक्षा २.८३२ हैक्टर, ३४९/१ रक्षा ०.८०९ हैक्टर एंव ३५४/१ रक्षा १.६१९ हैक्टर का अनावेदकगण को प्रथम अपर जिला व्यायालय के वाद कमांक १७ ए/०२ में पारित आदेश दिनांक २३-९-०२ से भूमिस्वामी घोषित किया है जिसके कारण उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित छहराते हुये सिविल व्यायालय के आदेश के कारण तहसीलदार द्वारा आवेदकगण के हित में ग्राम मेढेली स्थित भूमि सर्वे कमांक ३४८/१ रक्षा २.८३२ हैक्टर के अंश भाग कमशः हृदयलाल साहू का ०.२०० है पर, जगदीश प्रसाद का ०.२०० हैक्टर पर एंव प्रेमलाल का ०.२४० हैक्टर पर कब्जा दर्ज करना नियमानुकूल नहीं माना है। यह सही है कि माननीय प्रथम अपर जिला व्यायालय के वाद कमांक १७ ए/०२ में पारित आदेश दिनांक २३-९-०२ वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड भूमिस्वामी अनावेदकगण है, परन्तु मौके पर कब्जे की स्थिति अनुसार ग्राम मेढेली स्थित भूमि सर्वे कमांक ३४८/१ रक्षा २.८३२ हैक्टर के अंश भाग कमशः हृदयलाल साहू का ०.२०० है पर, जगदीश प्रसाद का ०.२०० हैक्टर पर एंव प्रेमलाल का ०.२४० हैक्टर का कब्जा प्रमाणित पाया गया है कब्जे का तथ्य एंव भूमिस्वामी स्वत्व के तथ्य अलग अलग प्रकार के तथ्य हैं तहसीलदार ने अनावेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है अपितु आवेदकगण उक्तानुसार भूमि पर वर्ष १९६०-६१ से कब्जेदार होना प्रमाणित हुये हैं, जिसके कारण तहसीलदार तदनुसार कब्जा दर्ज करने हेतु संहिता की धारा १२१ के अधीन स्वतंत्र है क्योंकि तहसीलदार ने उक्तांकित रक्षे पर कब्जा दर्ज करके खसरे के खाना नंबर ३ में अनावेदकगण के अभिलिखित भूमिस्वामी स्वत्व में दखलबदाजी नहीं की है अपितु खसरे के कैफियत के खाना नंबर १२में कब्जे की मात्र प्रविष्टि दर्ज करने के

आदेश दिये हैं। यदि आवेदकगण के सम्बन्ध में अनावेदक यह मानते हैं कि आवेदकगण ने उनके स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा किया है वह सक्षम व्यायालय में कब्जा ठटाने की कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र हैं परन्तु अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण क्रमांक 12/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-2-2006 में उक्त तथ्यों पर ध्यान दे न देते हुये आवेदकगण के हितों के विपरीत निर्णय लिया है इसी प्रकार अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण में आये वास्तविक तथ्यों से हटकर विपरीत अर्थ निकालते हुये आदेश दिनांक 23-5-07 पारित किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली क्वारा प्रकरण क्रमांक 12/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-2-2006 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा क्वारा प्रकरण क्रमांक 430/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-5-2007 दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा क्वारा प्रकरण क्रमांक 430/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-5-2007 एंव अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली क्वारा प्रकरण क्रमांक 12/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-2-2006 वृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव तहसीलदार सिंगरोली क्वारा प्रकरण क्रमांक 41 अ-6-अ/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2005 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।


(एस०एस०अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल, म०प्र०

गवालियर